नक्सलियों की कमर तोड़ने के लिए प्रदेश में नया दस्ता

- नक्सलियों के मूवमेंट पर रखेंगे नजर, पुलिस को देंगे सूचना
- प्रस्ताव को मिली मंजूरी

850 पद मंजूर किये गये हैं दस्ते के लिए | **25** हजार रुपए मासिक मानदेय भी दिया जाएगा | **50** -50 लाख रुपये की अतिरिक्त राशि दिया जाएगा पदक विजेता खिलाड़ियों को

नक्सल प्रभावित तीन जिलों के लिए विशेष सहयोगी दस्ते होंगे गठित

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 6 मई. देश के साथ ही प्रदेश में भी मार्च 2026 तक नक्सलवाद को पूरी तरह खत्म करने के केंद्र सरकार के संकल्प को पूरा करने के लिए राज्य सरकार ने भी एक कदम और आगे बढ़ा दिया है. अब प्रदेश के तीन नक्सल प्रभावित जिलों में विशेष सहयोगी दस्ते गठित होंगे.

इस दस्ते के लिए 850 पद मंजूर किये गये हैं. इस दस्ते में शामिल युवा गांव के ही होंगे और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में नक्सलियों के मूवमेंट पर नजर रखेंगे, जहां भी नक्सल गतिविधि की आशंका होगी, वे पुलिस और प्रशासन को सूचित करेंगे, जिससे कि नक्सलियों के खिलाफ तेजी से कार्रवाई की जा सके.

कैबिनेट ने मंगलवार को इस संबंध में पेश प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है. ये दस्ते नक्सल प्रभावित बालाघाट, मण्डला एवं डिण्डोरी में तैनात किये जाएंगे. ये नियुक्ति एक वर्ष के लिए होगी, दस्ते में शामिल युवाओं को 25 हजार रुपए मासिक मानदेय भी दिया जाएगा. दरअसल केंद्र सरकार ने जो लक्ष्य तय किया है उस हिसाब से अब महज एक वर्ष के भीतर प्रदेश से पूरी तरह नक्सल गतिविधियों को समाप्त कर दिया जाएगा.

अभयारण्य की सीमा से अलग होगी पचमढ़ी नगर की नजूल भूमिः कैबिनेट ने पचमढ़ी नगर की नजूल भूमि को अभयारण्य की सीमा से अलग करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. पचमढ़ी नगर का नजूल क्षेत्र जिसका रकबा 395.931 हेक्टेयर है, जो साडा के प्रशासनिक नियंत्रण में है, को पचमढी अभयारण्य की सीमा से बाहर करने का निर्णय लिया गया है. इसके पूर्व अधिसूचना 22 दिसम्बर 2017 द्वारा पचमढ़ी अभयारण्य की परिधि पर स्थित 11 ग्रामों को अभयारण्य से बाहर किया और कुछ ग्रामों को इन्क्लोजर में रखा गया है.

ये निर्णय भी लिए

नव गठित जिले मऊगंज, मैहर एवं पांढुर्णा में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अंतर्गत जिला आपूर्ति अधिकारी कार्यालय और निवाड़ी, मऊगंज, मैहर एवं पांढुर्णा में नाप-तौल कार्यालय स्थापित होंगे. तीन जिला आपूर्ति अधिकारी कार्यालय के लिए कुल 16 पद और 4 जिलों में नाप-तौल कार्यालय के लिए कुल 13 पद स्वीकृत.

जिला पेंशन कार्यालयों में पदों में कटौती होगी

प्रदेश के जिला पेंशन कार्यालयों में अब पदों में कटौती की जाएगी. पेंशनरों पेंश्रों की कम होती संख्या और केंद्रीयकृत व्यवस्था के चलते जिलों में अब लगातार मेनपॉवर की जरुरत कम होने लगी है, जिसे देखते हुए कैबिनेट ने ये निर्णय लिया है. निर्णय के तहत पेंशन प्रकरणों के निराकरण के लिए राज्य केंद्रीयकृत पेंशन प्रोसेसिंग सेल का गठन किया जाएगा. राज्य केंद्रीयकृत पेंशन प्रोसेसिंग सेल को पेंशन प्रकरणों के निराकरण से संबंधित समस्त प्रक्रिया के लिए अधिकृत किया जायेगा. संभागीय और जिला स्तर के कार्यालयों तथा सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों की सुविधा के लिए अस्थायी रूप से 2 वर्ष के लिए वर्तमान संभागीय और जिला पेंशन कार्यालयों को पेंशन समाधान केन्द्र के रूप में सीमित संरचना के साथ रखा जायेगा. पदों का युक्तियुक्तकरण किया जायेगा. इससे राज्य शासन पर अनावर्ती व्यय भार 5 करोड़ रूपये होगा.

पैरा- ओलम्पिक के विजेता को भी मिलेंगे एक करोड़ रुपए

पैरा-ओलम्पिक में पदक विजेता खिलाड़ियों को 50-50 लाख रुपये की अतिरिक्त राशि दिया जाएगा. जिससे कुल सम्मान राशि 1 करोड़ रुपये हो जाएगी. उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री द्वारा पैरा-ओलम्पिक खिलाडी सुश्री रूबिना फ्रांसिस और श्री कपिल परमार को पैरा-ओलम्पिक खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर 1 करोड़ रूपये की सम्मान राशि देने की घोषणा की थी. पेरिस, फ्रांस में आयोजित पैरा ओलम्पिक खेल, 28 अगस्त से 8 सितंबर 2024 में मप्र की खिलाड़ी सुश्री रूबिना फ्रांसिस ने शूटिंग खेल में कांस्य पदक एवं कपिल परमार ने ब्लाइंड जुडो खेल में कांस्य पदक अर्जित किया था.

ताई , भाई और युवा मेयर की ऊर्जा एक ही दिशा में !

भाजपा के संदर्भ में इंदौर की राजनीतिक तासीर अब बदल चुकी है. जहां कभी भाजपा के अंदर 'ताई और भाई' के बीच खींचतान की खबरें सुर्खियों में रहती थीं, वहीं अब 2023 के बाद से एक नया राजनीतिक संतुलन बनता दिख रहा है. आज इंदौर की राजनीति में स्थानीय शासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, महापौर पुष्यमित्र भार्गव और सांसद शंकर लालवानी,ये तीनों नेता पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन के मार्गदर्शन में शहर के विकास के लिए एकजुट नजर आ रहे हैं.

इस बदले हुए राजनीतिक समीकरण की सबसे सशक्त मिसाल है इंदौर की मेट्रो परियोजना. शुरुआती चरणों में जब मेट्रो रूट को लेकर चर्चाएं हो रही थीं, तब पलासिया से राजवाड़ा तक इसे अंडरग्राउंड करने का प्रस्ताव रखा गया. लेकिन सुमित्रा महाजन ने तकनीकी, ऐतिहासिक और व्यावहारिक कारणों के आधार पर यह सुझाव दिया कि इस हिस्से में मेट्रो को अंडरग्राउंड बनाना उचित नहीं होगा, यह शहर की पुरातात्विक विरासत, यातायात व्यवस्था और लागत तीनों को प्रभावित कर सकता है. ताई की इस स्पष्ट राय को तीनों प्रमुख नेताओं नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, महापौर पुष्यमित्र भार्गव और सांसद लालवानी ने न केवल सहमति दी, बल्कि इसे कार्यरूप भी दिया. नतीजतन पिछले दिनों नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा था कि यदि शहर के विकास और विरासत के लिए सरकार को थोड़ा नुकसान भी उठाना पड़े तो हमें मंजूर होगा.

इस सामूहिक सहमति ने यह संकेत दिया है कि अब इंदौर के नेता व्यक्तिगत रणनीति से ऊपर उठकर जनहित को प्राथमिकता दे रहे हैं. पहले जहां सार्वजनिक मंचों पर एक-दूसरे के निर्णयों पर सवाल उठाए जाते थे, आज वहीं मंच विकास की साझा योजनाओं के समर्थन में गूंजते हैं. दरअसल, इंदौर की जनता के लिए यह बदलाव केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक स्तर पर भी महत्वपूर्ण है. उन्हें यह भरोसा मिल रहा है कि जिन नेताओं को उन्होंने चुना है, वे अब एक टीम की तरह सोच रहे हैं और कार्य कर रहे हैं. राजनीतिक दृष्टि से भी यह भाजपा की परिपक्वता का संकेत है कि, जहां अनुभव, प्रशासनिक समझ और युवा नेतृत्व मिलकर शहर की आकांक्षाओं को दिशा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं. कुल मिलाकर, इंदौर की राजनीति अब 'मॉडल' बन रही है, जहां ताई का अनुभव, भाई की रणनीति और युवा मेयर की ऊर्जा मिलकर शहर के सपनों को आकार दे रहे हैं. इस त्रिकोण का चौथा कोण यानी संसद शंकर लालवानी भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं. दरअसल जिम्मेदार नेताओं का यह सिर्फ़ तालमेल नहीं ,बल्कि एक विज़न है,

जिसमें मतभेदों से ऊपर उठकर, इंदौर के भविष्य को प्राथमिकता दी जा रही है. अगर यह लय बनी रही, तो इंदौर न सिर्फ मध्य प्रदेश, बल्कि पूरे देश के लिए एक शहरी विकास की मिसाल बन सकता है.

उज्जैन की सभी निर्माणाधीन सड़कों का बनेगा डिजिटल मैप

कलेक्टर रोशन कुमार सिंह का एक और नवाचार, जीआइएस वेब पर अपलोड होंगे सिहस्थ की सड़कों के कार्य

- अब नहीं चलेगी निर्माण एजेंसियों की धांधताली

नवभारत न्यूज़

उज्जैन. महाकाल की नगरी का पूरा मास्टर प्लान वर्ष 2035 तक के लिए तैयार हो चुका है. टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ने जो मैप तैयार किया है वह भी अब ऑनलाइन हो चुका है. उसी में सिंहस्थ 2028 के मद्देनजर बनाई जाने वाली सड़कों को भी जीआइएस वेब के तहत अपलोड किया जाएगा. दरअसल जिलाधीश रोशन कुमार सिंह द्वारा इस तरह का एक और नवाचार किया जा रहा.

नवभारत से चर्चा में कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने बताया कि उज्जैन में सिंहस्थ की तैयारियां प्रारंभ हो चुकी है, जिसमें लगभग 30 से अधिक सड़कों का चयन किया गया है. जहां पर साधु, संत, श्रद्धालु और अतिथि अत्यधिक आवाजाही करेंगे, इनमें से कई सड़कें टू लेन - फोरलेन में भी तब्दील हो रही है. कुल मिलाकर सभी सड़कों को जीआइएस वेब पर डाला जाएगा.

टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की भूमिका

जिलेभर में जितने भी विकास कार्य निजी और सरकारी तौर पर किए जाते हैं, उसमें मास्टर प्लान के तहत टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से नक्शे अप्रूव्ड करना जरूरी होता है. सिंहस्थ क्षेत्र से लेकर निजी क्षेत्र तक में मास्टर प्लान की मदद ली जाती है. जीआईएस मैपिंग के तहत टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ने पूरा शहर समाहित किया है. यही कारण है कि जो नवाचार किया है उसमें टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की अहम भूमिका होगी.

सड़कों का अलाइनमेंट सेट होगा

टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के अधिकारी अंशुल गुप्ता ने नवभारत से चर्चा में बताया कि जिला प्रशासन सिंहस्थ सड़कों को लेकर क्या तैयारी कर रहा है इसकी जानकारी अभी हम तक नहीं आई है, हालांकि सड़कों का अलाइनमेंट सेट करने के लिए इस तरह का नवाचार किया जाना बेहद प्रशंसनीय कदम है जिससे कि निर्माण एजेंसीयो के ऊपर निर्भरता खत्म हो जाएगी और जिला प्रशासन को सीधे यह पता चल जाएगा कि किन सड़कों की क्या स्थिति है.

कंसल्टेंट द्वारा तैयार होगी स्कीम

उज्जैन में पीडब्ल्यूडी, नगर निगम, विकास प्राधिकरण पीआईयू, सेतु निगम, एमपीआरडीसी से लेकर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क विभाग, स्मार्ट सिटी जैसी कई निर्माण एजेंसियां सिंहस्थ में अनेकों कार्य कर रही है. इनमें से सिंहस्थ के अंतर्गत जो सड़के प्राथमिकता से तैयार की जाना है, उनके लिए कंसल्टेंट नियुक्त किए गए हैं. जो पूरी स्कीम तैयार करके जीआइएस वेब पर अपलोड करेंगे. एक क्लिक पर जिला प्रशासन को यह जानकारी प्राप्त हो जाएगी, जिसमें सारे आंकड़े समाहित होंगे कि उक्त सड़कों के निर्माण की क्या स्थिति है, सरकारी निर्माण एजेंसियो की धांधली, अफसरो व इंजीनियरों की लापरवाही भी पकड़ में आ जाएगी.

भारतीय खाद्य निगम
क्षेत्रीय कार्यालय, चेतक भवन, महाराणा प्रताप नगर, भोपाल (म.प्र.) 462011
दूरभाष: 0755-2573444, फैक्स : 0755-2573418, ईमेल: gmmp.fci@gov.in

क्र. एसएंडसी/13/एचटीसी/एनआईटी/2025/13 दिनांकः 07.05.2025

निविदा आमंत्रण सूचना

मध्य प्रदेश क्षेत्र में विभिन्न नियमित हैंडलिंग एवं परिवहन ठेकेदारों की नियुक्ति के लिए Government E Marketing Portal (URL:https://gem.gov.in) पर online प्रस्ताव आमंत्रित किये गये है निविदा के बारे में विस्तृत विवरण वेबसाइट www.fci.gov.in & www.gem.gov.in पर उपलब्ध विस्तृत एनआईटी एवं एमटीएफ में देखा जा सकता है । किसी विवाद की स्थिति में निविदा आमंत्रण सूचना का अंग्रेजी रूपांतरण मान्य/वैध होगा

महाप्रबंधक (क्षेत्र)

तेज आंधी और बारिश के साथ गिरे ओले

मध्यप्रदेश में अगले 72 घंटों में गरज-चमक के साथ तेज बारिश का अलर्ट

भोपाल, 06 मई. मध्य प्रदेश के मौसम में अगले 72 घंटों में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में गरज-चमक के साथ तेज बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की है.

वहीं गौरतलब है कि मंगलवार को भी प्रदेश के कई जिलों में तेज आंधी और बारिश देखने को मिली थी, जिसमें शाजापुर, नीमच और सीहोर जैसे जिलों में ओले भी गिरे थे. ग्वालियर सहित 16 जिलों में आज ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया गया है, जबकि भोपाल, इंदौर, जबलपुर, उज्जैन समेत 30 से अधिक जिलों में आंधी और बारिश का सिलसिला जारी रहने का अनुमान है. कुछ क्षेत्रों में हवा की रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है. मौसम विभाग के अनुसार, मंगलवार को ग्वालियर, श्योपुर, मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, मैहर, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडौरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा और पांढुर्णा जिलों में ओलावृष्टि की आशंका है.

वर्तमान में मध्य प्रदेश के मौसम को पश्चिमी विक्षोभ और विभिन्न चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र प्रभावित कर रहे हैं.

अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगातार नमी आने के कारण प्रदेश में अगले तीन दिनों तक इस तरह का मौसम बने रहने की संभावना है.

7 मई बुधवार को शहडोल, उमरिया, डिंडौरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी, मैहर, अनूपपुर, छिंदवाड़ा और पांढुर्णा में ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है. इसके अतिरिक्त, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, श्योपुर, मुरैना, भिंड, दतिया, विदिशा, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, सीधी, सिंगरौली, नर्मदापुरम, बैतूल, सीहोर, देवास, रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर, धार और बड़वानी, राजगढ़, सतना, रीवा, मऊगंज, शाजापुर, आगर-मालवा, नीमच, मंदसौर में हल्की बारिश और आंधी आ सकती है.

8 मई गुरुवार को भी मौसम का मिजाज बिगड़ा रहने का अनुमान है. बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, शिवपुरी, मैहर, शहडोल, अनूपपुर, पांढुर्णा, बैतूल, ग्वालियर, श्योपुर, मुरैना, भिंड, दतिया, मंडला, नर्मदापुरम, बुरहानपुर, खरगोन, रतलाम, रायसेन, सीहोर, हरदा, देवास, खंडवा, झाबुआ और अलीराजपुर में गरज-चमक के साथ बारिश का पूर्वानुमान जारी किया गया है.

प्रदेश के सबसे गर्म शहर

भोपाल	34.6
इंदौर	32.4
ग्वालियर	35.4
जबलपुर	37.6
रीवा	37.2
सागर	36.4

(तापमान डिग्री सेल्सियस में)

मौसम विभाग की अपील

मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने और आवश्यक सावधानी बरतने की अपील की है। तेज आंधी और बारिश के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहने और बिजली के खंभों से दूर रहने की सलाह दी गई है। किसानों को भी अपनी फसलों को संभावित नुकसान से बचाने के लिए उचित कदम उठाने के लिए कहा गया है।

दिल्ली में 50 से अधिक नाइजीरियन ड्रग तस्कर वर्तमान में हैं सक्रिय

- नाइजीरियन तस्कर जैकब ने रिमांड में उगले चौंकाने वाले राज
- घरों में ही बना लेते हैं एमडी ड्रग्स

नव भारत न्यूज

इंदौर. क्राईम की टीम द्वारा पिछले दिनों पकड़ाए गए नाइजीरियन तस्कर ने रिमांड के दौरान कई चौंकाने वाले राज उगले है. जिससे यह पता चला कि शहर के ड्रग्स नेटवर्क की कड़ी जब दिल्ली तक पहुंची है. आरोपी द्वारा उगले गए राज में पता चला कि देश की राजधानी में स्थित कुछ कॉलोनियों में 50 से अधिक नाइजीरियन ड्रग की तस्करी में सक्रिय हैं. आरोपी ने यह भी उगला कि कुछ आरोपी घरों में ही एमडी ड्रग्स बना लेते है. मामले में क्राईम ब्रांच आगे की कार्रवाई कर रही है.

पिछले दिनों क्राईम ब्रांच की पकड़ में आए दिल्ली में रहने वाले ड्रग्स तस्कर जैकब नानबूईके जैकब ने रिमांड के दौरान क्राईम ब्रांच के अधिकारियों के आगे चौंकाने वाले राज खोले है. आरोपी जैकब ने बताया कि दिल्ली के कृष्णापुरी सहित कुछ क्षेत्रों में बड़ी संख्या में नाइजीरियन नागरिक एमडी ड्रग्स का कारोबार कर रहे हैं. ये लोग बिजनेस वीजा पर भारत आते हैं, लेकिन वीजा खत्म होने के बाद भी गैरकानूनी रूप से यहीं टिक जाते हैं. इनमें से कुछ नाइजीरियन साइबर फ्रॉड जैसे अपराध में भी शामिल हैं. यह लोग बड़ी तादाद में एमडी ड्रग्स के निर्माण और तस्करी जैसे अपराधों में लिप्त है. पुलिस को यह भी पता चला कि इन तस्करों के पास एमडी ड्रग्स बनाने का पूरा फॉर्मूला मौजूद है, और वे किराए के मकानों या फ्लैट्स में अच्छी क्वालिटी की एमडी ड्रग्स तैयार कर लेते है. यही कारण है कि देशभर के अन्य छोटे बड़े तस्कर इनसे ड्रग्स मंगवाते हैं और स्थानीय बाजारों में बेचते हैं.

पहले भी पकड़ा जा चुका है एक नाइजीरियन

इंदौर क्राईम ब्रांच इससे पहले भी एंथोनी उर्फ मामा नामक नाइजीरियन को गिरफ्तार कर चुकी है, वह भी उसकी पत्नी के साथ के साथ मिलकर एमडी ड्रग्स तैयार करता था. वहीं एडीशनल डीसीपी क्राईम राजेश दंडोतिया का कहना है कि इंदौरक्राईम ब्रांच द्वारा किए गए बड़े खुलासे के बाद देशभर की पुलिस व अन्य एजेंसियों ने दिल्ली के ऐसे नेटवर्कस पर शिकंजा करते हुए कई जगह पर छापा मार कार्रवाई कर रही है.

AMBIT Finvest Pragati ke partner **AMBIT FINVEST PRIVATE LIMITED**
कॉर्पोरेट कार्यालयः कनकिया वॉल स्ट्रीट, 5वीं मंजिल, ए 506-510, अंधेरी-कुर्ला रोड, अंधेरी ईस्ट, मुंबई-400093

मांग नोटिस

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 ("अधिनियम") और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 ("नियम") के प्रावधानों के अंतर्गत

अधोहस्ताक्षरी अधिनियम के अंतर्गत एम्बिट फिनवेस्ट प्राइवेट लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा अधिनियम की धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नियम 3 के साथ, अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत मांग नोटिस जारी करते हुए निम्नलिखित उधारकर्ता(ओं) से उक्त नोटिस की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर संबंधित नोटिस में उल्लिखित राशि चुकाने का आह्वान किया गया है। नीचे हस्ताक्षरकर्ता का यथोचित मानना है कि उधारकर्ता(ओं) मांग नोटिस(ओं) की सेवा से बच रहे हैं, इसलिए नोटिस की सेवा नियमों के अनुसार चिपकाकर और प्रकाशित करके की जा रही है। मांग नोटिस(ओं) की सामग्री नीचे उद्धृत की गई है:

उधारकर्ता (ओं) का नाम	मांग नोटिस की तिथि और राशि
1.1. निर्भय सिंह सोलंकी 2. ब्रिगेडा ज्ञान सागर पब्लिक स्कूल समिति, 3. सुरेशचंद्र जी 4. ललिता सोलंकी 5. शर्मा मंजूबाई लैन नं. IND000000001927	23.04.2025. रु. 40,33,141.06/- (रुपये चालीस लाख तैंतीस हजार एक सौ इकतालीस रुपये और छह पैसे मात्र) दिनांकः 23.04.2025

बंधक अचल संपत्ति/संपत्तियों का विवरणः डायवर्टेड भूमि जिसका सर्वे नं. 315/6 पटवारी हल्का नं. 23/2, ग्राम बिरगोदा, तहसील, देपालपुर 453 115, जिला इंदौर है, जिसका स्वामित्व श्री निर्भय सिंह सोलंकी और श्री सुरेशचंद्र शर्मा के पास है, जो ज्ञान सागर पब्लिक स्कूल के पक्ष में है। उक्त संपत्ति की सीमाः - पूर्वः श्री गजराज सिंह की भूमि पश्चिमः देपालपुर गौतमपुरा रोड - उत्तरः श्री गजराज सिंह की भूमि दक्षिणः फील्ड रोड

ऋणकर्ता(ओं) को सलाह दी जाती है कि वे मांग नोटिस(ओं) का अनुपालन करें और इसमें उल्लिखित मांग राशि का भुगतान इस प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर लागू ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, बाउंस शुल्क, लागत और भुगतान की प्राप्ति की तिथि तक व्यय के साथ करें। ऋणकर्ता(ओं) को ध्यान देना चाहिए कि अऋद्धछ एक सुरक्षित ऋणदाता है और ऋणकर्ता(ओं) द्वारा प्राप्त ऋण सुविधा ऋणकर्ता(ओं) द्वारा गिरवी रखी गई अचल संपत्ति/संपत्तियों के विरुद्ध एक सुरक्षित ऋण है। यदि उधारकर्ता निर्धारित समय के भीतर अपनी देनदारियों का पूर्ण रूप से निर्वहन करने में विफल रहते हैं, तो एएफपीएल सुरक्षित परिसंपत्ति (संपत्तियों) को अपने कब्जे में लेने के लिए अधिनियम की धारा 13(4) के तहत सभी अधिकारों का प्रयोग करने का हकदार होगा, जिसमें बिक्री के माध्यम से उसे स्थानांतरित करना या अधिनियम और इसके नियमों के तहत उपलब्ध किसी अन्य उपाय को लागू करना और भुगतान प्राप्त करना शामिल है, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है। एएफपीएल को बिक्री या हस्तांतरण के अधिकार को लागू करने से पहले सुरक्षित परिसंपत्ति (संपत्तियों) को कुर्क करने और/या सील करने का भी अधिकार है। सुरक्षित परिसंपत्ति (संपत्तियों) की बिक्री के बाद, एएफपीएल को शेष बकाया राशि वसूलने के लिए अलग से कानूनी कार्यवाही शुरू करने का भी अधिकार है, यदि बंधक संपत्तियों का मूल्य एएमपीएल को देय बकाया को कवर करने के लिए अपर्याप्त है। यह उपाय किसी भी अन्य कानून के तहत एएफपीएल के लिए उपलब्ध सभी अन्य उपायों के अतिरिक्त और स्वतंत्र है। ऋणकर्ता(ओं) का ध्यान अधिनियम की धारा 13(8) की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसमें सुरक्षित परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में तथा अधिनियम की धारा 13(13) की ओर भी ध्यान दिलाया जाता है, जिसके तहत ऋणकर्ता(ओं) को अऋद्धछ की पूर्व लिखित सहमति के बिना सुरक्षित परिसंपत्तियों का निपटान करने या उनसे निपटने अथवा बिक्री, पट्टे या अन्यथा (व्यावसायिक प्रक्रिया के अलावा) किसी भी सुरक्षित परिसंपत्ति को हस्तांतरित करने से रोका/निषिद्ध किया जाता है तथा उपरोक्त का अनुपालन न करना उक्त अधिनियम की धारा 29 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। मांग नोटिस की प्रति नीचे हस्ताक्षरकर्ता के पास उपलब्ध है तथा ऋणकर्ता (ओं) यदि चाहें तो इसे नीचे हस्ताक्षरकर्ता से किसी भी कार्य दिवस पर सामान्य कार्यालय समय के दौरान प्राप्त कर सकते हैं।

दिनांकः 07.05.2025, स्थानः इंदौर

हस्ताक्षरकर्ता/- प्रशांत ओहाल प्राधिकृत अधिकारी
एम्बिट फिनवेस्ट प्राइवेट लिमिटेड

पुलिस बल तैनात | गांव में तनाव बढ़ता देख पुलिस ने कुछ युवकों को लिया हिरासत में और की पूछताछ

उज्जैन जिले में लवजिहाद के मामले, गांव बंद

नवभारत न्यूज़

घट्टिया (उज्जैन). समीपस्थ गांव बिछडोद व नजरपुर में लव जिहाद का मामला सामने आया है. गांव बंद रहा और पुलिस बल तैनात कर दिया गया है.

प्राप्त जानकारी के अनुसार समुदाय विशेष के युवकों ने मिलकर अनेक लड़कियों को अपने जाल में फंसाया. मामले का पर्दाफाश होने के बाद बिछडोद नगर में बाजार बंद हो गया. भारी पुलिस बल तैनात किया गया है. सकल हिन्दू समाज में उक्त मामले के प्रति आक्रोश व्याप्त है. बताया जा रहा है कि कई बालिकाएं नाबालिग है. जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि समुदाय विशेष के युवकों ने गैंग बनाकर नजरपूर व बिछडोद की बालिकाओं को अपने प्रेम जाल में फंसाकर उनके अश्लील वीडियो बना लिए थे. जिसकी जानकारी गांव के जागरूक लोगों को लगने पर उन्होंने एक लड़के से सख्ती से पूछताछ की व उसका मोबाइल चेक किया जिसमें अश्लील फोटो वीडियो पाए गए. जब ग्रामीणों ने सख्ती से बात की तो चोकाने वाले खुलासे हुए व पूरा मामला सामने आया कि 8 से अधिक लड़के इस जिहाद में संलिप्त है जिनके द्वारा भोली भाली मासूम लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फसाकर उनके वीडियो फोटो बना कर उन्हे ब्लैकमेल किया जा रहा है. गांव में तनाव बढ़ता देख पुलिस ने कुछ युवको को हिरासत में लिया है व पूछताछ जारी है.

उक्त मामले की जानकारी हिन्दूवादी संगठनों तक पहुची तो आक्रोश फेल गया. हिन्दूवादी संगठनों के लोगों ने बिछडोद पहुंचकर विरोध जताया. उक्त मामले के विरोध में ग्रामीणों ने सोमवार को ही बिछडोद बंद की घोषणा कर दी थी जिसके परिणामस्वरूप मंगलवार को बिछडोद पूर्णत: बंद रहा. स्थिति तनावपूर्ण होती देख बिछडोद व नजरपूर में भारी पुलिस बल तैनात किया गया. उज्जैन घट्टिया व राघवी आदि थानों का पुलिस बल तैनात किया गया. साथ ही हिन्दूवादी संगठनों ने घट्टिया थाना पहुंचकर उक्त मामले के प्रति आक्रोश जताया. हिन्दूवादी संगठनों के अनेक पदाधिकारी घट्टिया थाना पहुचे. एडिशनल एसपी गुरुप्रसाद पारासर व एसडीएम राजेश बोरासी सहित भारी पुलिस बल बिछडोद में मौजूद रहा.

Yellow Diamond **प्रताप स्नैक्स लिमिटेड**
सीआईएन: L15311MP2009PLC021746
पंजीकृत और कॉर्पोरेट कार्यालय: खसरा नंबर 378/2, नेमावर रोड, मकरंद हाउस के पास, पालदा, इंदौर- 452020, म.प्र., भारत
फोन: (91 731) 2437604 / 642; फैक्स: (91 731) 2437605
ई-मेल: complianceofficer@yellowdiamond.in; वेबसाइट: www.yellowdiamond.in

मार्च 31, 2025 को समाप्त तिमाही और वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का विवरण

मार्च 31, 2025 को समाप्त तिमाही और वर्ष के लिए कंपनी के लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों की लेखा परीक्षा समिति द्वारा समीक्षा और कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा 5 मई, 2025 को आयोजित अपनी संबंधित बैठकों में अनुमोदित किया गया।

मार्च 31, 2025 को समाप्त तिमाही और वित्तीय वर्ष के लिए पूर्ण रुप से ऑडिट किये गए वित्तीय परिणाम भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015, के विनियम 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंजों में दाखिल किया गया है और ये कंपनी की वेबसाइट www.yellowdiamond.in पर भी उपलब्ध है। इसे क्यूआर कोड स्कैन करके भी प्राप्त किया जा सकता है।

स्थान: इंदौर
दिनांक: मई 7, 2025

प्रताप स्नैक्स लिमिटेड
अमित कुमत
प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेंट प्रा. लि. हेतु लेसी एंगेज मीडिया प्रा.लि. के लिए आशुतोष उपाध्याय द्वारा 6/54, फिरोज गांधी प्रेस काम्प्लेक्स, इंदौर से प्रकाशित एवं नवभारत प्रेस भोपाल प्रा.लि. , फिरोज गांधी प्रेस कॉम्प्लेक्स इंदौर से मुद्रित. समूह संपादक क्रांति चतुर्वेदी*, *समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत जिम्मेदार, फोन/फैक्स- 4096718 RNI Reg. No.7390/60